राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

RNI NO. : MAHHIN/2019/77511

वर्ष 07 | अंक 11 | मुंबई : बुधवार 14 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 8 | कीमत : 03 रुपये

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

मुंबई : हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी, शिंदे सेना और एमआईएम गठबंधन की आलोचना की

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम धार्मिक मुद्दों को हवा देकर अपना राजनीतिक फायदा उठा रही हैं। वे हिंदू-मुस्लिम, मराठा-ओबीसी झगड़े कराकर लोगों को भड़काते हैं और सत्ता के लिए एक साथ आते हैं। हरी पतंग का मांझा भगवा होता है और धनुष का तीर हरा होता है। इन दोगले भाजपा, शिंदे सेना और एआईएमआईएम को नगर निगम चुनाव में सबक सिखाओ और कांग्रेस से बहुमत से जिताने की अपील करो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने यह किया है।

इस समय हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम दोनों ही हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि वे सत्ता की मलाई खाने के लिए एक साथ आते हैं। अकोट में भाजपा और एआईएमआईएम सत्ता के लिए एक हो गए हैं।

मुंबई : डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: 17.55 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 10 तस्कर गिरफ्तार

मुंबई : डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई), मुंबई जोनल यूनिट ने पिछले तीन दिनों में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हाईवे से लेकर एयरपोर्ट रनवे तक फैले ड्रग सिंडिकेट पर नकेल कसी गई, जिसमें कुल 522.138 किलोग्राम गांजा, 1.12 किलोग्राम कोकीन, 3.15 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड और 280 ग्राम एम्फेटेमिन जब्त किया गया। इनकी अनुमानित अवैध बाजार कीमत 17.55 करोड़ रुपए है। इन मामलों में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

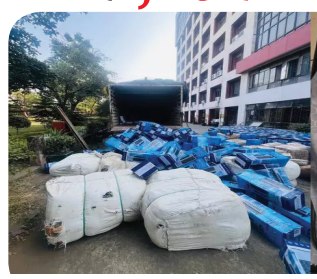

खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने नेशनल हाईवे-47 पर नागपुर के पास भगिम्हारी टोल प्लाजा पर एक ट्रक को रोका। जांच में कूलर, टेबल फैन और कंबल के कवर के नीचे छिपे 17 कार्टन मिले, जिनमें 100 पैकेट वाले 522.138 किलोग्राम गांजा था। इसकी बाजार कीमत 2.6 करोड़ रुपए आंकी गई।

गांजा एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया और ट्रक में सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एक गुप्त रात भर के ऑपरेशन में डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट परिसर से निकल रहे एक एयरपोर्ट कैटरिंग कंपनी के फूड ट्रक को रोका।ड्राइवर द्वारा यात्री सीट के पीछे छिपाकर रखा गया 3.15 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3.15 करोड़ रुपए है। आगे की जांच में एयरपोर्ट इकोसिस्टम के अंदर काम करने वाले सिंडिकेट के पांच सदस्य पकड़े गए। इनमें विमान सफाई स्टाफ शामिल था, जिसने टॉयलेट बिन में छिपी ड्रग्स निकाली, ड्यूटी मैनेजर जिसने सफाई स्टाफ को टारगेटेड फ्लाइट्स पर लगाया, और सिंडिकेट का मुख्य कोऑर्डिनेटर। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन भी जब्त किया गया।

मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में कचरा फेंकते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल; सिविक सेंस और एनवायरनमेंट की ज़िम्मेदारी पर नई बहस

मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में एक आदमी को लापरवाही से कचरा फेंकते हुए दिखाने वाला एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पब्लिक जगहों पर सिविक सेंस और एनवायरनमेंट की ज़िम्मेदारी पर नई बहस छिड़ गई है।

यह घटना तब सामने आई जब एक विदेशी टूरिस्ट ने गेटवे के पास समुद्र किनारे बनी सेफ्टी वॉल पर बैठकर इस हरकत को रिकॉर्ड किया। वीडियो में, विदेशी टूरिस्ट को

चुपचाप आस-पास का नजारा बनाते हुए देखा जा सकता है, तभी हेलमेट पहने एक आदमी एक औरत और एक बच्चे के साथ मौके पर आता है। कपड़े का बैग लिए हुए, वह आदमी थोड़ी देर रुकता है, बैग खोलता है और लापरवाही से उसका सामान, जो कथित तौर पर घर का कचरा है, सीधे समुद्र में खाली कर देता है।

ऐसा लगता है कि इस हरकत से वीडियो बनाने वाला आदमी हैरान रह जाता है।

''वह क्या था?'' विदेशी टूरिस्ट को यह कहते हुए सुना जा सकता है, जब वह आदमी कचरा फेंकता है और बिना किसी झिझक या पछतावे के चला जाता है। जैसे ही कैमरा उस आदमी की ओर जाता है जो औरत और बच्चे के साथ उस जगह से जा रहा है, विदेशी टूरिस्ट बताता है कि उसके सामने क्या हुआ। वीडियो खत्म होते ही वह कहता है, ''यह अच्छा नहीं है,'' और जो उसने देखा, उससे साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करता है। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया, जिसकी नेटिजन्स ने कड़ी आलोचना की। कई यूजर्स ने मुंबई के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट लैंडमार्क में से एक पर, खासकर एक विदेशी विज़िटर के सामने, कचरा फैलाने की इस खुलेआम हरकत पर शर्मिंदगी और गुस्सा दिखाया।

मुंबई कोस्टल रोड की भूमि सामान्यतः जनता के लिए खुली रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुंबई कोस्टल रोड (साउथ) के पास स्थित वह रीक्लेम्ड भूमि, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लैंडस्केपिंग और विकास कार्यों के लिए सौंपा गया है, सामान्य रूप से आम जनता के लिए खुली रहनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत निजी एजेंसियों को कोस्टल रोड के किनारे की रीक्लेम्ड भूमि पर लैंडस्केपिंग और मेंटेनेंस का काम दिया जाना था।

जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंद्राकर की खंडपीठ ने कहा कि 30 सितंबर 2022 के अपने पहले के आदेश में कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि इस रीक्लेम्ड भूमि का किसी भी प्रकार से आवासीय या व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता – न वर्तमान में और न ही भविष्य में। कोर्ट ने दोहराया कि यह भूमि केवल सार्वजनिक उपयोग और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से ही विकसित की जा सकती है। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ''धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (साउथ)'' परियोजना के अंतर्गत जो क्षेत्र कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसी

निजी संस्था को विकास के लिए दिया गया है, वह सामान्यतः जनता के लिए खुला रहेगा। केवल उन्हीं हिस्सों में अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जहां विकास या रखरखाव का कार्य चल रहा हो। ऐसे सभी कार्य बीएमसी के निर्देश और निगरानी में किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता जिपनेश नरेंद्र जैन ने आशंका जताई थी कि अगर रिलायंस जैसी कॉर्पोरेट संस्था को पूरा नियंत्रण दे दिया गया तो क्षेत्र का व्यावसायीकरण हो सकता है और आम लोगों की पहुंच सीमित हो सकती है। उन्होंने यह भी मांग की थी कि ऐसे कार्यों के लिए खुली निविदा प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि एनजीओ, आर्किटेक्ट और अन्य संस्थाएं भी भाग ले सकें। हालांकि, कोर्ट ने माना कि 2022 के आदेश से याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान हो चुका है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह इलाका निजीकरण या व्यावसायीकरण की ओर न जाए और जनता की पहुंच बनी रहे। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि कोस्टल रोड के किनारे की रीक्लेम्ड जमीन और प्रोमनेड को ''पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी'' और ''कोस्टल कॉमन्स'' घोषित किया जाए, ताकि इसे किसी निजी संस्था के दीर्घकालिक नियंत्रण में न दिया जा सके।

साथ ही, पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार से ऐसी नीति बनाने की मांग की गई थी जो इन क्षेत्रों को गैर-व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखे। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह क्षेत्र सामान्यतः जनता के लिए खुला रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का व्यावसायीकरण स्वीकार्य नहीं होगा।

मुंबई : चुनाव ड्यूटी और प्रचार के लिए 3400 गाड़ियां...

मुंबई : ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में चुनाव के लिए 3,400 से ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें ऑटो-रिक्शा, कार, टैक्सी, बस, टेम्पो और दूसरी कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं।मुंबई में चुनाव ड्यूटी और कैंपेन पर 3400 गाड़ियांहालांकि कई गाड़ियों को ऑफिशियली चुनाव ड्यूटी के लिए लिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में कारों और बसों को खास तौर पर कैंपेन के इस्तेमाल के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों से किराए पर लिया गया है।

रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र के बाहर रजिस्टर्ड 142 गाड़ियों झ खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की झ को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए चलने की कंडीशनल परमिशन दी गई है, जो पॉलिटिकल रैलियों और रोड शो को सपोर्ट करने के लिए शहर में आई हैं। कई नॉर्थ इंडियन नेता सिविक चुनावों के लिए कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए ये बाहर की गाड़ियां उनके साथ गई हैं। एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अधिकारी ने कहा, ''इन गाड़ियों को कुछ खास शर्तों के साथ परमिशन दी गई है। परमिट से लगभग ₹2.84 लाख का रेवेन्यू मिलेगा। गाड़ियों के इस बेड़े में एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगी खुली जीप, मिनी ट्रक और वैन शामिल हैं। पार्टी कार्यकताओं ने कहा कि ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कल्चरल प्रोग्राम और वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए हाई-विज़िबिलिटी आउटरीच के लिए किया जा रहा है।9 जनवरी तक के ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि अंधेरी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने 99 गाड़ियों को परमिशन दी है, जो मुंबई के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा है। इसके बाद मुंबई सेंट्रल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने 27 गाड़ियों को, वडाला रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने 16 को और बोरीवली रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने एक गाड़ी को परमिशन दी है।इसके अलावा, कैंपेन के लिए इस्तेमाल हो रही 244 लोकल रजिस्टर्ड गाड़ियों को परमिशन दी गई है, जिससे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को परमिट फीस के तौर पर ₹4.68 लाख और मिले हैं। चुनाव से जुड़े कैंपेन के लिए किसी भी गाड़ी के इस्तेमाल के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना जरूरी है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा, ''परमिट समय पर जारी करने के लिए, मुंबई में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफिस ने 'स्पेशल सेल' बनाए थे, जिन्होंने चुनाव कैंपेन के लिए इस्तेमाल हो रही इन गाड़ियों को परमिशन दी।'' कैंपेन की स्ट्रेटेजी में एलईडी स्क्रीन लगी गाड़ियों पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा विज़िबिलिटी के लिए अक्सर रेलवे स्टेशन, बस डिपो और मार्केट एरिया के पास खड़ा किया जाता है। अब तक, 69 फोर-व्हीलर और 68 थ्री-व्हीलर को डिजिटल एडवरटाइजिंग की परमिशन दी गई है, जिससे अलग से ₹1.72 लाख का रेवेन्यू मिला है।डिजिटल आउटरीच की तरफ बदलाव के बावजूद, कैंपेन के पुराने तरीके जारी हैं, जिसमें ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों पर लगे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल शामिल है। इस बीच, प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने चुनाव के दौरान चुनाव स्टाफ और राजनीतिक उम्मीदवारों को लाने-ले जाने के लिए सरकार को लगभग 2,500 बसें झ एसी और नॉन-एसीदोनों झ और लगभग 450 कारें दी हैं।

नगर निगम चुनाव में जासूसों की एंट्री

सियासी दल एक दूसरे के राज जानने के लिए इन्हें लगा रहे हैं काम पर

मुंबई : मुंबई और महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों का माहौल जैसे-जैसे गर्म होता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों की रणनीति भी और ज्यादा हाइटेक होती जा रही हैं. अब चुनावी मैदान सिर्फ रैलियों, पोस्टरों और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे एक 'सीक्रेट गेम' भी चल रहा है. इसमें प्राइवेट जासूसों की अहम भूमिका भी दिखाई दे रही है.

चुनावी हलकों में चर्चा है कि कई राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निजी जासूसों की सेवाएं ले रहे हैं. मकसद साफ है. यह जाना जा रहा है कि कौन नेता बगावत की तैयारी में है, कौन पाला बदल सकता है और किस उम्मीदवार की कमजोर नस को दबाया जा सकता है.

भारत की पहली महिला जासूस मानी जाने वाली रजनी पंडित के मुताबिक चुनावों के साथ प्राइवेट जासूसों की मांग अचानक बढ़ जाती है. उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि टिकट न मिलने से नाराज नेता ही नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से परेशान लोग भी संपर्क करते हैं. चुनावों की घोषणा के बाद से ऐसे मामलों में तेजी आ जाती है.

कितनी होती है फीस

वहीं राजनीतिक मिशन पर लगने वाले इन जासूसों की फीस भी कम नहीं है. जांच की जटिलता के हिसाब से निजी जासूसी एजेंसियां 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक चार्ज कर रही हैं. इन जांचों में उम्मीदवार का पूरा बैकग्राउंड खंगालना, सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखना, करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों की जानकारी जुटाना शामिल है.

मुंबई : संरक्षित तोते की प्रजातियों की तस्करी के लिए तीन लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई : एक नाबालिग समेत तीन लोगों के खिलाफ, कथित तौर पर सुरक्षित तोते की प्रजाति को गैर-कानूनी तरीके से रखने और उसकी तस्करी करने का केस दर्ज किया गया है। शनिवार को मिली एक टिप पर कार्रवाई करते हुए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने शहर के येरवदा इलाके में कई जगहों पर मिलकर छापे मारे और सुरक्षित प्रजाति के छह ज़िंदा तोते बचाए। ये छापे शांतिनगर, लक्ष्मीनगर और टिंगरेनगर (येरवदा) में फॉरेस्ट अधिकारियों और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों की एक जॉइंट टीम ने मारे, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेटर (टेरिटोरियल) आशीष ठाकरे की गाइडेंस में थे।टीम को पाँच एलेक्जेंडराइन तोते (जिन्हें स्थानीय तौर पर पहाड़ी पोपट कहा जाता है) और एक रोज-रिंग्ड तोता बिना किसी वैलिड परमिट के गैर-कानूनी तरीके से रखे जांच चल रही है।फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार, एलेक्जेंडराइन पैराकीट और रोज-रिंग्ड पैराकीट दोनों वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के शेड्यूल (2) के तहत लिस्टेड हैं, जो उन्हें दुर्लभ और सुरक्षित प्रजातियों की कैटेगरी में रखता है।

इन पक्षियों को रखना, बेचना या खरीदना एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है।पुणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, विशाल चव्हाण ने कहा, ''सुरक्षित पक्षियों की प्रजातियों का गैर-कानूनी व्यापार बायोडायवर्सिटी के लिए एक गंभीर खतरा है। हमारी टीम ने भरोसेमंद जानकारी पर तेजी से कार्रवाई की और इन तोतों को सफलतापूर्वक बचाया।

टिंगरेनगर (येरवदा) में फॉरेस्ट अधिकारियों और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों की एक जॉइंट टीम ने मारे, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेटर (टेरिटोरियल) आशीष ठाकरे की गाइडेंस में थे। ये छापे शांतिनगर, लक्ष्मीनगर और और बेचे जा रहे मिले।

सभी छह पक्षियों को ज़िंदा बचा लिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कस्टडी में ले लिया गया। नतीजों के आधार पर, तीनों आरोपियों के खिलाफ वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के नियमों के तहत फॉरेस्ट ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, और वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क की आगे की

मुंबई : पार्टी का एकमात्र फोकस विकास पर है – अजीत पवार

मुंबई : इस साल 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनकी पार्टी का एकमात्र फोकस विकास पर है। उन्होंने आगे कहा कि उनका मकसद सिर्फ. वादे करना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करना भी है। उन्होंने बताया कि मुंबई जैसे महानगरों में प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। पवार ने ठउढ के घोषणापत्र में बताई गई मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताया और शहरी महाराष्ट्र में शासन, गठबंधन और नागरिक चुनौतियों से जुड़े सवालों के जवाब दिए।

पवार ने कहा, ''इस साल के घोषणापत्र का सबसे महत्वपूर्ण नया पहलू शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी स्पष्ट और केंद्रित प्रतिबद्धता है। लोगों को साफ और पर्याप्त पीने का पानी मिलना चाहिए, रोजाना साफ-सफाई बनाए रखी जानी चाहिए, सड़कें अच्छी हालत में होनी चाहिए, और ट्रैफिक को कुशलता से मैनेज किया जाना चाहिए।

सभी नागरिकों के लिए मेडिकल सुविधाएं सुलभ और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।'' उन्होंने आगे कहा कि मुंबई जैसे महानगरों में प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है।

उन्होंने कहा, ''हम प्रदूषण पर भी खास ध्यान दे रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या बन गई है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये चिंताएं हमारे घोषणापत्र में साफ तौर पर बताई गई हैं।

हमारा मकसद सिर्फ. वादे करना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है।'' इस आलोचना का जवाब देते हुए कि सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद ऐसी नागरिक सुविधाएं पहले क्यों नहीं दी गईं, पवार ने पिंपरी-चिंचवड़ में किए गए अपने काम का हवाला देते हुए अपने रिकॉर्ड का बचाव किया। उन्होंने कहा, ''मैंने पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम में लगभग 25 साल तक सेवा की है। उस दौरान किए गए काम को कोई भी वेरिफाई कर सकता है। किसी को वहां किए गए विकास को देखना चाहिए और कैसे पिंपरी-चिंचवड़ को सबसे अच्छे मैनेज किए गए शहरों में से एक के रूप में पहचान मिली।''

मुंबई : महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टियों ने आइडियोलॉजी छोड़ दी है और उन्हें सिर्फ.पावर में दिलचस्पी है - अकबरुद्दीन ओवैसी

मुंबई : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टियों ने आइडियोलॉजी छोड़ दी है और उन्हें सिर्फ.पावर में दिलचस्पी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल लीडर्स को दशकों से पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने के बावजूद मुस्लिम और पिछड़े समुदाय सबसे नीचे बने हुए हैं। 15 जनवरी को होने वाले सिविक बॉडी इलेक्शन से पहले राज्य के मराठवाड़ा इलाके के छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली को एड्रेस करते हुए, तेलंगाना के विधायक ने महाराष्ट्र में रूलिंग और अपोज़िशन दोनों पार्टियों की बुराई की।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रीअलाइंस ने आइडियोलॉजी की कमी को सामने ला दिया है। उन्होंने कहा, ''पहले, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाया था। बाद में, अजित पवार ने भाजपा के साथ अलायंस किया, और एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में शिवसेना का बंटवारा हुआ, और भाजपा के साथ गठजोड़ हो गया। कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। ये पार्टियां सिर्फ. पावर चाहती हैं और उनका सेक्युलरिज्म या हिंदुत्व से

कोई लेना-देना नहीं है।'' ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए आवाज उठा रही है और साथ ही दलितों और पिछड़े समुदायों के लिए भी बोल रही है। उन्होंने कहा, ''यह देश उन लोगों का भी है जो टोपी पहनते हैं और अपना चेहरा ढकते हैं और उन लोगों का भी जो अपने माथे पर तिलक लगाते हैं।''

खुद को भारतीय और मुस्लिम दोनों बताते हुए, ओवैसी ने कहा कि उन्हें अपनी पहचान पर गर्व है, लेकिन आरोप लगाया कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उन्हें बहुत बुरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुसलमानों के पिछड़ेपन का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि समुदाय ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तक के नेताओं का इस उम्मीद से साथ दिया था कि उनके इलाकों का विकास होगा और गरीबी कम होगी। उन्होंने कहा, ''आज, स्कूल छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं।

वे हर सेक्टर में पीछे हैं।''ओवैसी ने आरोप लगाया कि एक के बाद एक सरकारों ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया और उन्हें शिक्षा और रोजगार के मौकों से वंचित रखा। उन्होंने कहा, ''इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछड़े वर्गों को साथ लेकर चल रही है और सरकार से कह रही है कि हमारी हालत खराब है।'' उन्होंने कहा कि न केवल मराठा समुदाय, बल्कि पूरा मराठवाड़ा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। उन्होंने मराठा समुदाय और कार्यकर्ता मनोज जरांगे से क्षेत्रीय पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की।

मुंबई मनपा चुनाव : 4521 अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी पुलिस कार्रवाई

मुंबई। बीएमसी ने चुनावी कामों में हिस्सा नहीं लेने वाले 4,521 अधिकारियों और कर्मचारियों पर आज से पुलिस कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने चुनावी कार्य में हिस्सा न लेने वाले 6,871 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इनमें से 2,350 अधिकारी और कर्मचारी बाद में चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो गए, जबकि बार-बार सूचना देने के बावजूद प्रशिक्षण, मतदान प्रक्रिया अथवा सौंपे गए चुनावी कर्तव्यों में उपस्थित न रहने वाले कर्मचारियों पर मनपा अब कार्रवाई करना

शुरू कर दिया है। बता दे कि मुंबई मनपा का चुनाव 15 जनवरी और मतगणना 16 जनवरी को होगी।

चुनावी कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का पहले और दूसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। चुनावी कर्तव्य के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण में उपस्थित रहना अनिवार्य था। बावजूद इसके प्रशिक्षण सत्र या चुनावी ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वालों को 10 जनवरी को अंतिम अवसर दिया गया था। अतिरिक्त मनपा आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही करना गंभीर अपराध माना जाता है। संबंधित 4,521 कर्मचारियों को नोटिस देकर उनके कार्यालयों में जाकर पुलिस के माध्यम से 12 जनवरी से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करना, दंडात्मक कार्रवाई और विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल होगी।

मुंबई : महा विकास अघाड़ी ने अब तक डिपोर्टेशन की संख्या पर सवाल उठाया...

मुंबई : वीकेंड में महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए कैंपेन अपने चरम पर पहुंचने के साथ ही, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से मुक्त करने का भरोसा दिलाया, लेकिन, विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने अब तक डिपोर्टेशन की संख्या पर सवाल उठाया और पूछा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पिछले दस साल से क्या कर रही थी। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों से पहले भाजपा-शिवसेना-आरपीआई (अठावले) गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी करते हुए फडणवीस, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने कहा, ''हम मुंबई को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से मुक्त करेंगे।''

फडणवीस के साथ डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी थे। फडणवीस ने कहा, ''पिछले एक से डेढ़ साल में (एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस) ने अच्छा काम किया है...सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया गया है... असल में, महाराष्ट्र सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से एक एआई -बेस्ड टूल डेवलप कर रही है, जो हमें बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और (बाद में) उनके डिपोर्टेशन में मदद करेगा।'' उनके मुताबिक, यह अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है और 60 परसेंट भरोसेमंद हो गया है। उन्होंने कहा, ''हम 100 परसेंट तक जाएंगे और फिर इसे डिप्लॉय करेंगे,'' और कहा कि बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ करते हैं। उन्होंने कहा, ''फिर वे (मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में) चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स हासिल करते हैं...वे हमारे जैसे दिखते हैं...वे हमारी तरह बोलते हैं (और घुलमिल जाते हैं),'' हालांकि, उन्होंने दोहराया, ''हम बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का पता लगाकर उन्हें डिपोर्ट करेंगे।''

हालांकि, कांग्रेस ने फडणवीस से उन बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं का डेटा देने को कहा जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। एआईसीसी सेक्रेटरी और महाराष्ट्र कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन सचिन सावंत ने कहा, ''अगर सरकार ने सच में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान की है, तो उसे आंकड़े जारी करने चाहिए।'' दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) विधायक उद्धव ठाकरे ने कहा, ''वे 12 साल से केंद्र में राज कर रहे हैं...वे राज्य में हैं...वे कैसे आए।'' इसके अलावा, उन्होंने कुछ म्युनिसिपल काउंसिल में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ अलायंस करने के लिए भाजपा और शिवसेना का भी मजाक उड़ाया।

विकास केवल तस्वीरें दिखाने से नहीं होता - सांसद श्रीकांत शिंदे

मुंबई : शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि विकास केवल तस्वीरें दिखाने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए उचित योजना, कार्यान्वयन और सभी अनुमतियां और एनओसी आवश्यक हैं। उन्होंने विशेष रूप से मुंबई की कोस्टल रोड परियोजना का उदाहरण देते हुए बताया कि यह परियोजना 2022 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में सवालों के घेरे में रही थी, लेकिन अब इसे पूरा कर जनता के लिए उपयोगी साबित किया गया है। सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में केवल योजनाओं और आरेखों को दिखाना पर्याप्त नहीं होता। परियोजनाओं का सही ढंग से लागू होना, कानूनी मंजूरी, पर्यावरण एवं तकनीकी अनुमतियां और स्थानीय प्रशासन के साथ

समन्वय जरूरी है। उन्होंने कोस्टल रोड को उदाहरण बताते हुए कहा कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा कर मुंबईवासियों को सड़क, यातायात और परिवहन सुविधाओं में सुधार का लाभ मिला है। शिंदे ने कहा कि मुंबई में कोस्टल रोड जैसी परियोजनाएं न केवल यातायात के लिए आवश्यक हैं, बल्कि इससे शहर के विकास में भी तेजी आई है। यह सड़क मार्ग स्थानीय लोगों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। सांसद ने यह भी बताया कि 2022 में परियोजना पर उठाए गए सवालों के बावजूद उचित योजना, कार्यान्वयन और आवश्यक अनुमतियों के माध्यम से इसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे विकास कार्यों में समय, संसाधनों और समर्पित प्रशासन की आवश्यकता होती है।

कोस्टल रोड परियोजना के तहत मुंबई के पश्चिमी तट के साथ सड़क मार्ग विकसित किया गया, जिससे मुख्य क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई और शहर में ट्रैफिक बोझ कम हुआ। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं केवल दृश्य प्रभाव या प्रचार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे स्थायी लाभ देने वाली होती हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे विकास कार्यों को केवल आलोचना के आधार पर नहीं आंकें, बल्कि परियोजना के वास्तविक लाभ और कार्यान्वयन पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कोस्टल रोड जैसी परियोजनाएं लंबे समय में शहर के जीवन स्तर और आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि शिवसेना और सरकार का उद्देश्य मुंबईवासियों के जीवन में सुधार लाना और शहर को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

दुनिया को अराजकता में झोंकते ट्रंप...

वेनेजुएला में अमेरिका की एकतरफा सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को चौंकाने का काम किया। शायद ऐसा पहली बार देखने को मिला कि किसी देश के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित उनके आवास से उठाकर अगवा कर लिया गया। निकोलस मादुरो के साथ अमेरिका की लंबी खटपट थी, लेकिन तमाम देशों सहित संयुक्त राष्ट्र उन्हें वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देते रहे। भारत भी ऐसे देशों में शामिल रहा। अमेरिका और खासतौर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस दादागीरी के पक्ष में सुविधाजनक दलीलें गढ़ी हैं। मादुरो पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप है। ऐसा कुछ भी हो, लेकिन इससे किसी शक्तिशाली देश को यह गुंजाइश नहीं मिल जाती कि वह ऐसे आरोपित को पकड़ने के लिए दूसरे देश में सैन्य छापेमारी वाली कार्रवाई करे। पाकिस्तान के एबटाबाद में दुर्दांत आतंकी ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाने की कार्रवाई ऐसे मामलों में अपवाद की श्रेणी में आती है, लेकिन यही पैमाना मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर नहीं लागू किया जा सकता। बदली हुई परिस्थितियों में वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। अमेरिका ने उन पर दबाव डाला है कि उसकी मनमानी को मानती रहें और खासतौर से तेल एवं गैस के मामले में अमेरिकी निदेर्शों का पालन हो। वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार है।

ट्रंप इसी भंडार पर नियंत्रण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि केवल अमेरिकी और चुनिंदा यूरोपीय कंपनियां ही इस दक्षिण अमेरिकी देश के तेल बाजार के बड़े खेल की अहम खिलाड़ी बनी रहें। उन्होंने यही संकेत दिए हैं कि वे रूस और चीन को वेनेजुएला में किसी भी भूमिका से बाहर रखना चाहते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका का हस्तक्षेप कुछ वर्षों पहले अफगानिस्तान और इराक में ऐसे ही दखल से काफी अलग है। स्पष्ट है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में विफलता और इराक में सामने आई दुश्वारियों से सबक सीखा है कि ऐसी गलतियों से बचा जाए। अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। वैश्विक स्तर पर यह मान्यता थी कि अमेरिका के पास ऐसा करने का ठोस आधार है, क्योंकि तब उस पर एक भयावह आतंकी हमला हुआ था। सैन्य कार्रवाई से अफगानिस्तान में तालिबान का तो पतन हो गया, पर उसके और अलकायदा के बड़े आतंकी पाकिस्तान भागने में सफल रहे। तालिबान ने पाकिस्तान के समर्थन से अफगानिस्तान में आकार ले रही नई व्यवस्था के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। यह व्यवस्था अमेरिका और नाटो की सहायता से ही स्थापित हुई थी। अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी तब एक अंतरराष्ट्रीय बल के गठन की अनुमति दी थी। हालांकि अफगानिस्तान की नई व्यवस्था और अमेरिका मिलकर भी विरोधियों से पार नहीं पा सके।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK
LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE
SHARE
COMMENT
SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अबू आजमी का तंज...

मुंबई : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के हालिया बयान पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपनी अंदरूनी कलह और साजिशों के कारण खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है। भिवंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान अबू आजमी ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कांग्रेस की मौजूदा स्थिति की तुलना टीपू सुल्तान के दौर से कर दी।

अबू आजमी ने कहा, ''टीपू सुल्तान क्यों हारे थे? इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उनकी फौज में ही बहुत ज्यादा साजिशें चल रही थीं। कुछ लोग गद्दार बन गए, कुछ मुखबिर बन गए और नतीजा यह हुआ कि टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा।'' उन्होंने आगे कहा कि आज कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है, जहां पार्टी के भीतर ही विश्वास की कमी और आपसी खींचतान उसे कमजोर कर रही है। समाजवादी पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व बार-बार अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकताओं को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब किसी संगठन में अंदरूनी एकता नहीं होती और हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में लगा रहता है, तो पार्टी का नुकसान तय होता है। अबू आजमी के मुताबिक, कांग्रेस इस समय बाहरी विरोधियों से ज्यादा अपनी अंदरूनी राजनीति से जूझ रही है। अबू आजमी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का इतिहास आजादी की लड़ाई से लेकर देश के निर्माण तक रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में पार्टी अपने मूल मुद्दों से भटक गई है। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर लड़ने के बजाय कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। सपा नेता ने साफ शब्दों में कहा, ''कांग्रेस खुद को ही बर्बाद कर रही है। किसी को बाहर से कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो उसे कमजोर कर रहे हैं।'' उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कांग्रेस समय रहते आत्ममंथन नहीं करती और संगठनात्मक सुधार नहीं लाती, तो भविष्य में उसे और भी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अबू आजमी के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी दलों के बीच गठबंधन और तालमेल को लेकर चचार्एं चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान न सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठाता है, बल्कि विपक्षी एकता की चुनौतियों को भी उजागर करता है। कुल मिलाकर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अबू आजमी की यह प्रतिक्रिया विपक्षी राजनीति में बढ़ती तल्खी और अंदरूनी असहमति को दशार्ती है, जिसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. के खातों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर लगी रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील

मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. के खातों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर लगी रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इन बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं।

बैंकों ने दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अनिल अंबानी और उनकी कंपनी को राहत देते हुए सभी मौजूदा और भविष्य की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी।

एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि बैंक आरबीआई के अनिवार्य दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन कर रहे हैं और वर्षों बाद गहरी नींद से जागे हैं। सोमवार को चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बैंकों ने दलील दी कि खातों को फ्रॉड घोषित करने का आधार बना फॉरेंसिक ऑडिट पूरी तरह वैध है।

बैंकों का कहना है कि बीडीओ एलएलपी की ओर से तैयार रिपोर्ट में फंड की हेराफेरी और दुरुपयोग के गंभीर निष्कर्ष दर्ज हैं। बैंकों ने यह भी कहा कि अनिल अंबानी ने केवल तकनीकी आधार पर फॉरेंसिक ऑडिट को चुनौती दी थी और एकल पीठ का आदेश गलत और असंगत है। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 जनवरी को सूचीबद्ध कर दिया है।

ठाणे: स्कूल प्रिंसिपल पर चुनाव ड्यूटी के ऑर्डर मना करने पर केस दर्ज...

ठाणे: ठाणे के ब्रह्मांड में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 15 जनवरी को होने वाले ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनावों से पहले इलेक्शन डिपार्टमेंट के जारी इलेक्शन ड्यूटी ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया।ठाणे के स्कूल प्रिंसिपल पर इलेक्शन ड्यूटी ऑर्डर मना करने पर केस दर्ज हुआपुलिस के मुताबिक, ठाणे में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल विमलेश सिंधु ने ळटउ अधिकारियों के इलेक्शन ड्यूटी के नोटिस और

अपॉइंटमेंट ऑर्डर को बार-बार लेने से मना कर दिया और स्कूल से किसी भी टीचर या स्टाफ मेंबर को पोलिंग से जुड़े काम के लिए भेजने से भी मना कर दिया। इसके बाद, उन पर एक पब्लिक सर्वेंट के जारी ऑर्डर को न मानने के लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 223 के तहत केस दर्ज किया गया। चुनावों को आसानी से कराने के लिए, सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट बॉडीज के साथ-साथ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टीचर और स्टाफ को रेगुलर तौर पर पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया जाता है।इस बीच, ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर और चीफ इलेक्शन ऑफिसर सौरभ राव ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट जगहों और लोगों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण और सही तरीके से वोटिंग कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी कि 14 और 15 जनवरी को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात जो कर्मचारी गैरहाजिर रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राव ने आगे कहा कि सिंधु के खिलाफ केस स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन से जुड़े ऑर्डर का पालन कराने के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक दर्ज किया गया था।

मुंबई : पानी का संकट: भिवंडी के लोग टैंकरों पर आश्रित, अनियमित जल आपूर्ति का असर

मुंबई : गर्मी के महीने शुरू होने से पहले ही, भिवंडी के बड़े हिस्से पीने के पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अनियमित और कम प्रेशर वाली सप्लाई की वजह से लोगों को प्राइवेट टैंकरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे चल रहे नगर निगम चुनाव के मौसम में लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। अनियमित सप्लाई से शिकायतें बढ़ रही हैं भिवंडी में अनियमित और कम पानी की सप्लाई एक बार फिर एक बड़ी समस्या बन गई है, कई मोहल्लों में पानी सिर्फ. देर रात को ही आता है और वह भी बहुत कम प्रेशर पर। लोगों की शिकायत है कि पानी का कम बहाव ओवरहेड टैंक भरने के लिए भी काफी नहीं है, जिससे परिवारों को पीने के पानी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है।

आधी रात पानी की दिक्कत

कई इलाकों में, पानी सिर्फ. आधी रात से सुबह 2 बजे के बीच ही सप्लाई होता है, जिससे लोगों को रात में जागकर जितना थोड़ा-बहुत पानी जमा करना पड़ता है, उसे जमा करना पड़ता है। इस वजह से, कई हाउसिंग सोसाइटियों के लिए टैंकर का पानी ही एकमात्र भरोसेमंद ऑप्शन बन गया है, जिससे उनके महीने के खर्चे बढ़ रहे हैं। चुनावों में पानी की कमी पर रोशनी नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, वोटर घर-घर जाकर उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं और लंबे समय

से चली आ रही पानी की कमी के तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। इस समस्या ने शहर के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। कई लोग, खासकर हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग, पानी की कमी जैसी लगातार नागरिक समस्याओं के कारण भिवंडी से कल्याण, ठाणे, मुलुंड और यहां तक कि बोरीवली भी चले गए हैं। कई व्यापारी भिवंडी में अपना कारोबार चलाते रहते हैं, लेकिन बेहतर बुनियादी सुविधाओं के कारण मुंबई या ठाणे के उपनगरों में रहना पसंद करते हैं।

अशोक नगर सबसे ज्यादा प्रभावित

अशोक नगर में स्थिति खास तौर पर गंभीर है, जहां नगर निगम ने हाल ही में सप्लाई बेहतर करने की उम्मीद में पुरानी पाइपलाइनों को नई पाइपलाइनों से बदल दिया है। अजीब बात यह है कि लोगों का कहना है कि नई पाइपलाइनें बिछाए जाने के बाद से समस्या और भी खराब हो गई है। लोगों ने कम प्रेशर की शिकायत की अशोक नगर में बिल्डिंग नंबर 15 हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी तात्यासाहेब पंगारे ने कहा कि इलाके में सुबह 12 बजे से 2 बजे के बीच सिर्फ दो घंटे पानी आ रहा है, और वह भी बहुत कम प्रेशर पर। उन्होंने कहा, ''कम से कम एक घंटे के लिए प्रेशर इतना कम होता है कि टैंक बिल्कुल नहीं भरते। कई सोसाइटियों में, लोगों को रोजाना मुश्किल से 20 मिनट इस्तेमाल करने लायक पानी मिलता है।''

इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें बनी हुई हैं

एक और रहने वाले, प्रफुल गोसरानी ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन के काम के दौरान एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई थी, लेकिन बिजली कनेक्शन न होने की वजह से वह महीनों से चालू नहीं हुई है, जिससे संकट और बढ़ गया है। भविष्य के समाधान में देरी इस बीच, सिविक अधिकारियों ने कहा कि अमृत स्कीम के तहत अशोक नगर में एक बड़ी पानी की टंकी बनाई जा रही है, लेकिन इसे चालू होने में कम से कम दो से तीन साल लगेंगे। मजे की बात यह है कि इस इलाके में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इस वादे

नागपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत तय, गडकरी बोले- पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे

नागपुर : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। एक टॉक शो में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव उन्हें चुनाव जैसा लग ही नहीं रहा है। गडकरी के अनुसार, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा और अब असली सवाल यह है कि क्या पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। गडकरी ने कहा कि आज की राजनीति विचारधारा से ज्यादा सत्ता केंद्रित हो गई है। उन्होंने राजनीति को सुविधा की राजनीति और प्रतिबद्धता की राजनीति में बांटते हुए कहा कि पहले कार्यकर्ता बिना किसी अपेक्षा के पार्टी से जुड़े रहते थे, लेकिन अब सत्ता में रहने वाली पार्टी में जाने का चलन बढ़ गया है। उन्होंने इसे इंपोर्ट-एक्सपोर्ट राजनीति करार दिया। गडकरी ने नागपुर में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर का चेहरा बदल चुका है। सड़क, फ्लाईओवर, बुनियादी ढांचे और स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में नागपुर देश के सबसे साफ और सुंदर शहरों में शामिल होगा।

साकीनाका पुलिस ने एक ऐसे गैंग का किया पदार्फाश; "बैंक अकाउंट किट" सप्लाई करने का आरोप

मुंबईः साकीनाका पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पदार्फाश किया है, जिस पर इल्लीगल गेमिंग और बेटिंग ऐप्स, एपीके फाइल स्कैम और दूसरे ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल साइबर फ्रॉड को जाने-माने बैंकों के ''बैंक अकाउंट किट'' सप्लाई करने का आरोप है। गैंग के तीन मेंबर को शनिवार सुबह साकीनाका के एक होटल से गिरफ्तार किया गया।साकीनाका पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक किट सप्लाई रैकेट का पदार्फाश किया, तीन गिरफ्तारगिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिनाजुद्दीन अब्दुल पिलाकल, सूरज दिलीप दवंडे और आशीष शिवकुमार पाल के तौर पर हुई है।

एक लोकल कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया।पुलिस के मुताबिक, किट में डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, पासवर्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट थे, जो कथित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स को दिए गए थे ताकि वे पीड़ितों को ठगने के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट ऑपरेट कर सकें। एपीके फाइल स्कैम में, पीड़ितों को लिंक या मैसेज के जरिए मैलिशियस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल करने के लिए फंसाया जाता है, जिससे फ्रॉड करने वाले फोन, बैंकिंग डिटेल्स और ओटीपी तक रिमोट एक्सेस पा लेते हैं। अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड पर होटल आइकॉन में संदिग्ध गतिविधि की टिप मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। सुबह करीब 4 बजे रेड मारकर कमरा नंबर 108 से पिलाकल और दवंडे को गिरफ्तार किया गया। लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए।पूछताछ के दौरान, दोनों ने राजेश बी, अयान उर्फ मकसूद शेख और सौरव उर्फ आनंद शर्मा समेत अपने दूसरे साथियों के नाम बताए। आशीष पाल को बाद में कथित तौर पर लुकआउट के तौर पर काम करने के लिए हिरासत में लिया गया। शक है कि गैंग ने कई बैंक अकाउंट खोले थे और राज्यों में साइबर फ्रॉड करने वालों को किट सप्लाई की थीं।साकीनाका के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''हमने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी का पता लगा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितनी किटें और किसे बांटी गईं।''

मुंबई : 124 करोड़ की संपत्ति के मालिक, बनना चाहते हैं मुंबई के नगरसेवक...

मुंबई : बीएमसी चुनावों के मुंबई में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। मुंबई के चुनावी दंगल में यूं तो कई बड़ी हस्तियां हैं। इनमें अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की बेटियां भी शामिल हैं लेकिन वार्ड 226 से चुनाव लड़ रहे मकरंद नार्वेकर सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में 124.4 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति का ब्योरा दिया है। नार्वेकर एक बार फिर से मुंबई के नगरसेवक यानी पार्षद बनने के लिए मैदान में कूदे हैं, हालांकि बीते नौ सालों में उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है।

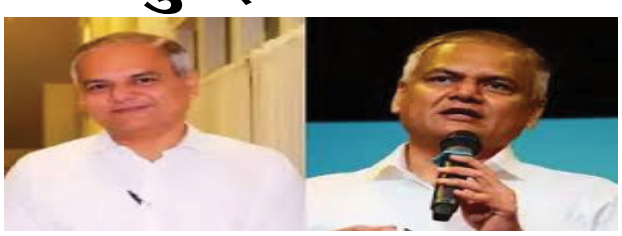

पिछले दिनों नार्वेकर तब सुर्खियों में आए थे, जब उनके भाई और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर विपक्षी उम्मीदवार को पर्चा वापस लेने की धमकी देने के आरोपों से घिरे थे। मकरंद नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के छोटे भाई हैं। मकरंद नार्वेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) वार्ड नंबर 226 से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के अनुसार मकरंद नार्वेकर की संपत्ति (जिसमें उनकी पत्नी की संपत्ति भी शामिल है) नौ साल पहले की तुलना में 1,868 प्रतिशत बढ़ी है। हालांकि उनकी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 2017 में बीजेपी के टिकट पर नगर निगम चुनाव लड़ते समय, उन्होंने 6.3 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। 2012 में जब उन्होंने पहली बार एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नगर निगम चुनाव लड़ा था, तो उनकी संपत्ति 3.67 करोड़ रुपये की थी। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक उनकी कुल आय 2.77 करोड़ रुपये है।

मुंबई : एसईसी ने लाडकी बहिन योजना के अग्रिम भुगतान पर लगाई रोक

मुंबई : राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने महानगरपालिका चुनाव के दौरान महाराष्ट्र सरकार को लाडकी बहिन योजना की अग्रिम भुगतान जारी करने पर रोक लगा दी है। एसईसी ने यह कदम विपक्षी दल के नेताओं की शिकायत के बाद उठाया है। विपक्ष का आरोप था कि प्रस्तावित धन वितरण का समय 15 जनवरी को होने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों से पहले महिला मतदाताओं को प्रलोभन देने के समान है। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा था कि लाभार्थियों को 14 जनवरी को दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर 3,000 रुपये पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इसके बाद विपक्ष ने एसईसी से इसकी शिकायत की थी।

झारखंड सीएम सोरेन करेंगे यूरोप दौरा, ऑक्सफोर्ड और दावोस में करेंगे शैक्षणिक और आर्थिक चर्चा

रांची (एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महीने के अंत में अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर यूरोप जाएंगे। उनके कार्यक्रम में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह दौरा झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ किया जा रहा है।

ऑक्सफोर्ड में सोरेन सेंट जॉन्स कॉलेज और ऑल सोल्स कॉलेज सहित कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा, वे ब्लावटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में सार्वजनिक नीति और शासन पर चर्चा करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस दौरे से झारखंड में विकास कार्यक्रमों के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करने में मदद मिल सकती है।

स्विट्जरलैंड में सोरेन दावोस में डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे, जहां वैश्विक आर्थिक और नीति निर्धारण से जुड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा।

इस दौरान झारखंड की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मनरेगा विरोध अभियान शुरू किया। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि 'मनरेगा बचाओ' अभियान के तहत उपवास, जन जागरूकता, नुक्कड़ नाटक और धरना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार के नए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम के विरोध में यह अभियान शुरू किया गया है। इस दौरे से झारखंड सरकार के वैश्विक मंच पर छवि निर्माण और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास को बल मिलने की उम्मीद है।

इसरो ईओएस-एन1 'अन्वेषा' जासूसी सैटेलाइट करेगा लॉन्च, डीआरडीओ ने किया तैयार

यह भारत को रक्षा, आपदा प्रबंधन, खेती और पर्यावरण निगरानी में बड़ी मजबूती देगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग एक उन्नत तकनीक है जो सैकड़ों प्रकाश बैंड्स के जरिए धरती की सतह की बेहद सटीक पहचान करती है। इसरो का ईओएस-एन1 'अन्वेषा' सैटेलाइट, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है, भारत को रक्षा, आपदा प्रबंधन, खेती और पर्यावरण निगरानी में बड़ी मजबूती देगा। यह तकनीक रणनीतिक योजना के साथ-साथ आम जनजीवन से जुड़े क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभाएगी। इसरो पीएसएलवी-सी62 मिशन के जरिए ईओएस-एन1 'अन्वेषा' सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक सैटेलाइट सीमित रंगों के आधार पर धरती की तस्वीरें लेते हैं, जबकि हाइपरस्पेक्ट्रल तकनीक सैकड़ों बेहद संकरे प्रकाश बैंड्स को रिकॉर्ड करती है। ये बैंड्स दृश्य प्रकाश से लेकर इंफ्रारेड तक फैले होते हैं, जिससे हर वस्तु की एक विशिष्ट 'लाइट फिंगरप्रिंट' तैयार होती है। धरती पर मौजूद हर वस्तु, मिट्टी, पानी, वनस्पति या मानव निर्मित ढांचे, रोशनी के साथ अलग-अलग व्यवहार करती है। इन विशेष पैटर्न्स को वैज्ञानिक स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी से मिलाते हैं, जिसे जमीन पर स्पेक्ट्रोरैडियोमीटर जैसे उपकरणों से तैयार किया जाता है। इसके बाद इस डेटा को जीआईएस और 3डी मैपिंग सिस्टम के साथ जोड़कर विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।

हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक योजना बनाने में अहम भूमिका निभाती है। यह जमीन के प्रकार की पहचान कर सैन्य वाहनों और सैनिकों के लिए सुरक्षित मार्ग तय करने में मदद करती है। यह नकली कैमोफ्लाज, छिपे हथियारों और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में भी सक्षम है। इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं है। खेती में फसलों की सेहत पर नजर रखने, आपदाओं के दौरान प्रभावित इलाकों की त्वरित पहचान, राहत और बचाव कार्यों और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।

12 जनवरी को प्रस्तावित अन्वेषा सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। इसके साथ ही यह आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और त्वरित निर्णय प्रणाली को नई गति देगा। इस मिशन से अंतरिक्ष तकनीक अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि देश और समाज के व्यापक हित में काम कर रही है। यह लॉन्च भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है।

जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के फैसले का विपक्षी दलों ने किया स्वागत

स्टालिन ने एक उच्चस्तरीय सलाहकार परिषद के गठन का किया आग्रह

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार की तरफ से आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के फैसले का विपक्ष ने एक सुर में स्वागत किया है। मोदी सरकार की तारीफ करने वालों में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से लेकर कांग्रेस के सांसद तक शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार का यह फैसला जनगणना में जातिगत गणना, डेटा-आधारित सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम साबित होगा। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला पिछले कई सालों से चल रही राजनीतिक बहस का नतीजा माना है।

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने आगामी राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय सलाहकार परिषद के गठन का आग्रह किया है। स?टालिन ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से साक्ष्य आधारित सामाजिक न्याय और नीति निर्माण के प्रति तमिलनाडु की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि कई राज्यों में व्याप्त गहरी सामाजिक गतिशीलता और जाति संरचनाओं को देखते हुए जाति जनगणना एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है। उन्होंने आगाह किया कि यदि इसे सावधानीपूर्वक नहीं संभाला तो यह प्रक्रिया अनपेक्षित सामाजिक तनावों को जन्म दे सकती है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के फैसले का स्वागत है। यह डेटा-आधारित सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम है, जिसकी मांग विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की नीतियों पर इसके प्रभावों को देखते हुए केंद्र को गलतियों और कमियों से बचने के लिए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह लेनी चाहिए।

यूएपीए कानून के तहत खालिद और शरजील को नहीं मिल सकी जमानत

-ओवैसी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, बोले- इस कानून का उन्होंने विरोध किया था

अमरावती (एजेंसी)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस कड़े यूएपीए के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है, उसे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था। यह बात ओवैसी ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र के अमरावती में एक जनसभा में कही।

उन्होंने कहा कि चुनाव में धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग वास्तव में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के दुश्मन हैं, क्योंकि वे वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि खालिद और शरजील दोनों को गैरकानूनी गतिविधियां की धारा के आधार पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

ओवैसी ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने यूएपीए पेश किया था और संसद में इसका विरोध करने वाले वे यानी खुद ओवैसी एकमात्र व्यक्ति थे। मैंने ही सबसे पहले कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल पुलिस मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों और उन बुद्धिजीवियों के खिलाफ करेगी जो सरकार की नीतियों को समझते और उनका विरोध करते हैं। आज जो हुआ वह आप देख ही सकते हैं, इन दोनों बच्चों को उस कानून में आतंकवाद की परिभाषा के कारण जमानत नहीं मिल पाई।

ओवैसी ने कहा कि खालिद और शरजील पांच साल से जेल में बंद हैं, वहीं एल्गर परिषद मामले में आरोपी 85 साल के स्टेन स्वामी की इसी कानून के कारण जेल में मौत हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में जब यूएपीए में संशोधन किया गया था, तब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का समर्थन किया था, जो अब निर्दोष लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन भागीदारी के क्रम का हवाला देते हुए पांच अन्य लोगों को जमानत दे दी थी।

वहीं, नागपुर में ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे, तो घर पर बुलडोज़र चलेगा... बीजेपी हो, अजीत पवार या एकनाथ शिंदे ये सभी पार्टियां आपको डराकर आपका वोट हासिल करना चाहती हैं। मजलिस आपको कह रही है कि अपनी पॉलिटिकल एजेंसी बनाइए।

प्रदूषण समस्या पर बोली कांगेस- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कागजी बनकर रह गया

-जयराम ने सीआइईए की अध्ययन रिपोर्ट का दिया हवाला

नई दिल्ली (एजेंसी)। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा, कि सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) को लेकर अपने एक बयान में कहा, कि यह अब नोशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (कागजी प्रोग्राम) बनकर रह गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम ने रविवार को जारी बयान में कहा, कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन ने इस बात की पुष्टि हुई है, कि वायु गुणवत्ता अब पूरे देश के लिए एक संरचनात्मक संकट बन चुकी है। उन्होंने कहा, यह लंबे समय से भारत के लिए सबसे खुला रहस्य है, कि देश के अधिकांश हिस्सों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, और सरकार की ओर से इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

क्या कहती है सीआरईए की रिपोर्ट

सीआरईए द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत के लगभग 44 प्रतिशत शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। इन शहरों में पांच वर्षों से अधिक समय तक हवा में पीएम 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से ऊपर बना हुआ है। इस अध्ययन में कुल 4,041 नगरों में से 1,787 शहरों को प्रदूषण की गंभीर चपेट में पाया गया है।

गहन समीक्षा और सुधार की आवश्यकता

कांग्रेस महासचिव जयराम ने कहा, कि एनसीएपी का नाम भले ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम रखा गया हो, लेकिन यह एक कागजी योजना बनकर रह गई है। अब इसकी गहन समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से यह भी कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदमों की सख्त आवश्यकता है।

प्रदूषण रोकने की मांग

कांग्रेस पार्टी ने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार से कई महत्वपूर्ण सुधार की मांग की है। जयराम रमेश ने कहा कि एनसीएपी के लिए आवंटित फंड में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एनसीएपी का बजट 25,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए और इसे देश के सबसे प्रदूषित 1,000 शहरों और कस्बों में लागू किया जाए। इसके अलावा, जयराम रमेश ने एनसीएपी को कानूनी आधार देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यह योजना अपनी प्राथमिकताएँ मुख्य प्रदूषण स्रोतों पर केंद्रित करे, विशेष रूप से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के प्रदूषण मानकों को कड़ा किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी बिजली संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सलफराइजर (एफजीडी) 2026 तक अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं।

कांग्रेस सांसद जयराम ने यह भी कहा, कि सरकार ने संसद में दो बार प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव को कमतर दिखाने की कोशिश की है और सरकार के इन प्रयासों को लेकर कांग्रेस ने इसे अक्षमता और लापरवाही का परिणाम करार दिया है।

'हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं..' माही विज और नदीम के लिंकअप की खबरों पर बोली सलमान खान की बहन

माही विज अपने लेटेस्ट पोस्ट की वजह से सुर्खियों में छा गई हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने एक लंबा चौंड़ा पोस्ट शेयर कर अपने दोस्त नदीम को बर्थडे विश किया था. माही ने जैसे ही पोस्ट शेयर किया वैसे ही लोगों ने नदीम के संग उनका नाम जोड़ना शुरू कर दिया.

बता दें जय भानुशाली संग तलाक के बाद से एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. ऐसे में माही ने ट्रोल करने वालों की जमकर क्लास लगाई. इसके अलावा अंकिता लोखंडे और जय भानुशाली भी उन्हें सपोर्ट किया. इसी बीच अब सलमान खान की बहन अर्पिता खान भी माही के सपोर्ट में उतर गई हैं.

अर्पिता ने माही विज को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है.उन्होंने लिखा,'नदीम अगर आप जैसे इंसान को भी बुरा-भला कहा जा सकता है, तो मुझे हैरानी होती है कि हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं.'नदीम के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि सलमान खान के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं नदीम.

भाईजान का बर्थडे हो या कोई फैमिली फंक्शन नदीम को उनके साथ कई बार स्पॉट किया जा चुका है.

सलमान खान के अलावा उनके परिवार के संग भी नदीम का काफी अच्छा रिश्ता है. इसके अलावा माही विज और जय भानुशाली के भी काफी अच्छे दोस्त हैं नदीम.इस एक्स कपल की बेटी नदीम को अब्बा कहकर बुलाती है. नदीम के बर्थडे के मौके पर माही और जय की बेटी तारा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था,' हैप्पी बर्थडे अब्बा'. ऐसे में इस बात को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई कि आखिर तारा नदीम को अब्बा क्यों कह रही है. इस तरह की बातों ने माही विज को काफी तकलीफ पहुंचाई.

माही ने सुनाई खरी-खोटी

इस वजह से उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी भड़ास निकाली. माही ने कहा कि कई सालों से वो नदीम के बर्थडे पर पोस्ट शेयर करती आ रही हैं. नदीम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं. माही ने कहा कि जय और उनका फैसला था कि तारा नदीम को अब्बा बोलेगी. माही ने ये भी कहा कि गंदगी फैलाने वाले लोगों पर थू है.

हॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर ने की प्रियंका चोपड़ा की तारीफ

तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके म्यूजिक कंपोजर Ricky Kej ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा जिससे ज्यादातर लोग सहमत होंगे। उन्होंने सबका ध्यान भारत की एक ऐसी एक्ट्रेस की तरफ खींचा है जिसे हम ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते-प्रियंका चोपड़ा। हम सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। भारत को देसी गर्ल पर गर्व है लेकिन शायद हॉलीवुड स्टार रिकी कैज को ऐसा नहीं लगता। हाल ही में म्यूजिक कंपोजर ने प्रियंका की तारीफ की और कहा कि प्रियंका को उनके ही देश में उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता जैसा करना चाहिए।

रिकी ने शनिवार को अपने हैंडल पर लिखा, 'वह किसी भी जेनरेशन की एकमात्र इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने हॉलीवुड और ग्लोबली सच में धूम मचाई है, उन्होंने बताया कि प्रियंका ने न सिर्फ बॉलीवुड के ज्यादातर बेहतरीन लोगों के साथ काम किया है, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ भी काम किया है। इस लिस्ट में सेठ गॉर्डन की 2017 की एक्शन कॉमेडी बेवॉच में ड्वेन जॉनसन (जिसमें उन्होंने मुख्य विलेन का रोल निभाया था), लाना वाचोव्स्की की 2021 की साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स में कियानू रीव्स, रॉबर्ट रेड्फ्रिज की 2020 की सुपरहीरो फिल्म वी कैन बी हीरोज में पेड्रो पास्कल, रूसो ब्रदर्स के 2023 के अमेजन प्राइम वीडियो स्पाई थ्रिलर शो सिटाडेल में स्टेनली टुची और रिचर्ड मैडेन और हाल ही में, पिछले साल इल्या नैशुलर की अमेजन प्राइम वीडियो एक्शन कॉमेडी हेड्स ऑफ स्टेट में जॉन सीना और इदरीस एल्बा शामिल हैं।

धुरंधर के बाद 'उल्फत रहमान' सौम्या टंडन की निकली लॉटरी, इस बॉलीवुड फिल्म में हुई एंट्री!

सौम्या टंडन 'भाबी जी घर पर हैं' से पॉपुलर हुई थीं। मगर उन्हें दुनियाभर में मशहूर करने का श्रेय धुरंधर को जाता है। साढ़े तीन घंटे की फिल्म में सौम्या का रोल छोटा लेकिन दमदार था। धुरंधर में रहमान डकैत को थप्पड़ मारने वाले सीन से सौम्या टंडन सोशल मीडिया पर छा गई थीं। लोगों ने उनकी भूमिका को खूब सराहा और अब इसका नतीजा यह निकला कि एक्ट्रेस को एक और बड़ी फिल्म मिल गई है।

धुरंधर के बाद सौम्या टंडन की किस्मत ऐसी चमकी कि उन्हें एक और बॉलीवुड फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। ऐसी चर्चा है कि वह सूरज बड़जात्या की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म ये प्रेम मोल लिया में नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए सूरज बड़जात्या अपने रोमांटिक जॉनर की ओर वापसी कर रहे हैं।

ये प्रेम मोल लिया मूवी में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाएं निभाएंगी। पिंकविला के मुताबिक, अब इस फिल्म में सौम्या टंडन की भी एंट्री हो गई है। हालांकि, फिल्म में एक्ट्रेस का क्या रोल होगा, अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। मगर कहा जा रहा है कि फिल्म में उनका रोल प्रभाव छोड़ने वाला होगा। यह एक रोमांटिक जॉनर की मूवी है। सूरज बड़जात्या ने इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया है।

सौम्या टंडन ने अपना करियर टीवी सीरियल ऐसा देस है मै मेरा से शुरू किया था। इसके बाद वह मेरी आवाज को मिल गई रोशनी, डांस इंडिया डांस (होस्ट) समेत कई शोज में होस्टिंग और एक्टिंग की। सौम्या को रातोंरात स्टारडम भाबी जी घर पर हैं से मिली थी। इस सीरियल में वह अनीता भाभी के किरदार में छा गई थीं। सौम्या टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन फिल्मों में उन्हें खास ऑफर नहीं मिला। उन्होंने करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट (करीना की बहन) से डेब्यू किया था। वह वेलकम टू पंजाब में भी नजर आ चुकी हैं। बड़े पर्दे पर सौम्या को आदित्य धर की धुरंधर से सफलता मिली।

रोड रोलर के नीचे आने से सुपरवाइजर की मौत!

मुंबई : पुणे से सटे चिंचवड इलाके से एक दिल दलाने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क निर्माण का काम करने के दौरान सुपरवाइजर की रोड रोलर के नीचे कुचले जाने से मौत हो गई है। ये पूरी घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल सुपरवाइजर की मौत के बाद से स्थानीय लोग हैरान हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक यह हादसा शनिवार दोपहर 4 बजे के करीब हुआ। यहां शहर के आकुंडी गंगा नगर इलाके में हादसा उस समय हुआ जब एक निजी कंपनी के दो कर्मी सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान सुपरवाइजर रोड रोलर के पीछे चल रहा था, तभी अचानक से रोड रोलर पीछे की दिशा में चलने लगा। इसी दौरान थोड़ी सी लापरवाही की वजह से देखते ही देखते उसने अपने लोहे के चक्के से सुपरवाइजर को रौंद डाला। इस घटना में सुपरवाइजर की मौके पर ही मौत होने गई। इस दर्दनाक हादसे की सारी हकीकत घटनास्थल पर मौजूद एक दुकान के कैमरे में कैद हो गी। स्थानीय व्यक्ति प्रभु कंगने ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुझे कॉल आया कि गंगानगर रोड पर ऐसी घटना हुई है तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा। हालांकि मेरे घटनास्थल पर आने से पहले ही स्थानीय लोग उनके वहां से लेकर अस्पताल चले गए थे।

विदेशी यात्रियों के साथ एयरपोर्ट स्टाफ भी शामिल

मुंबई कस्टम्स का गांजा, सोने की तस्करी के मामलों में भंडाफोड़

मुंबई : मुंबई कस्टम ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ और सोने की तस्करी के कई मामलों का खुलासा किया है। इन कार्रवाइयों में विदेशी यात्रियों के साथ-साथ एयरपोर्ट स्टाफ की संलिप्तता भी सामने आई है। एयरपोर्ट कमिश्नरेट द्वारा विकसित खुफिया जानकारी के आधार पर 08 जनवरी 2026 को हाइड्रोपोनिक गांजा तस्करी के कई मामले दर्ज किए गए।

पहला मामला

08 जनवरी 2026 को 03 अलग-अलग मामलों में कुल 44.059 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 44.059 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह मादक पदार्थ बैंकॉक से विभिन्न उड़ानों के जरिए मुंबई पहुंचे 08 यात्रियों के पास से बरामद किया गया। सभी आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

दूसरा मामला

विशेष खुफिया सूचना के आधार पर 01 अन्य मामले में 950 ग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 0.95 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह गांजा बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से बरामद किया गया, जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।

सोना तस्करी के मामले

पहला सोना मामला: 02 जनवरी 2026

02 जनवरी 2026 को दर्ज एक मामले में 1,300 ग्राम 24 कैरेट सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये है।इस मामले में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट यात्री द्वारा यह सोना एयरपोर्ट पर तैनात एक सेल्स एसोसिएट को सौंपा गया था। जांच के बाद एयरपोर्ट स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है।

दूसरा सोना मामला: 07 जनवरी 2026

07 जनवरी 2026 को दर्ज एक अन्य मामले में 1,450 ग्राम 24 कैरेट सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1.84 करोड़ रुपये बताई गई है।

यह सोना एक बांग्लादेशी ट्रांजिट यात्री द्वारा सीएसएमआई एयरपोर्ट के डोमेस्टिक डिपार्चर एरिया में स्थित फैबइंडिया काउंटर पर कार्यरत एएमआरपीएल स्टाफ को सौंपा गया था। इस मामले में बांग्लादेशी यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई कस्टम्स ने बताया कि इन सभी मामलों में तस्करी नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और एयरपोर्ट स्टाफ की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। आगे और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया गया है।

मुंबई पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए साथ आए - राज ठाकरे

मुंबई : शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने नगर निकाय चुनावों के लिए रविवार को एक संयुक्त रैली की. उन्होंने कहा कि मुंबई के सामने आ रहे 'खतरे' के कारण उनका राजनीतिक पुनर्मिलन हुआ है. उद्धव ने कहा कि उन्होंने और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी मानुष, हिंदुओं और महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया है. मराठी वोट बैंक को लक्ष्य करते हुए राज ने कहा कि मुंबई पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए वह और उद्धव एक साथ आए हैं.उन्होंने कहा, ''यह मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है. अगर उन्होंने अब कोई गलती की, तो लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे.'' राज के बाद रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा मुंबई का नाम बदलकर ''बंबई'' रखना चाहती है. उन्होंने इसके लिए तमिलनाडु

वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर महिला को जलाने के 35 साल पुराने मामले में आरोपी बरी

मुंबई : वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर कथित तौर पर एक महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी देशमंद मिरांडा (६४) को बरी कर दिया है, क्योंकि मूल दस्तावेज खो गए हैं और प्रमुख गवाहों की मौत हो चुकी है। १९९० में हुई इस घटना के बाद से आरोपी फरार था, उसे पिछले साल १२ सितंबर को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता नतालिन, मिरांडा की दोस्त वैष्ठनोट की बहन थी। मामला नतालिन के बहनोई, जोसेफ उर्फ जोबो पॉल कौटिन्हो ने दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि नतालिन के पति की घटना से ११ साल पहले मृत्यु हो गई थी और वे एक छोटी बेटी को पीछे छोड़ गए थे।

कौटिन्हो की शिकायत के अनुसार, ११ नवंबर १९९० को वे अपने घर पर थे, तभी उन्होंने एक पड़ोसी को नतालिन के घर की ओर भागते हुए देखा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने नतालिन को गंभीर रूप से झुलसा हुआ पाया। उसे इलाज के लिए तुरंत सायन अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि, १५ नवंबर, १९९० को कौटिन्हो ने दावा किया कि नतालिन ने उसे बताया था कि मिरांडा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिससे मिरांडा क्रोधित हो गया और उसने उसे आग लगा दी। कौटिन्हो ने दावा किया कि नतालिन ने उसे बताया कि जब उसे अस्पताल ले जाते समय मिरांडा ने उसे धमकी दी थी कि वह इस घटना का खुलासा न करे, अन्यथा वह उसकी मां के पैर काट देगा।

मूल दस्तावेज नहीं किए थे पेश

मिरांडा को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और उसी वर्ष ६ दिसंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी बीच, नतालिन की १६ नवंबर को मौत हो गई। जमानत पर रिहा होने के बाद मिरांडा फरार हो गया। अक्टूबर २०२५ में, जब अदालत ने मुकदमा शुरू करने का पैष्ठसला किया, तो पता चला कि अभियोजन पक्ष ने मूल एफआईआर, पंचनामा, पुलिस दस्तावेज या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं की थी। अभियोजन पक्ष ने कौटिन्हो और नतालिन की बेटी से पूछताछ की, लेकिन वे चश्मदीद गवाह नहीं थे।

मुंबई : प्रेमी ने प्रेमिका को खुश करने के लिए ऐसा गिफ्ट दिया; दोनों पर मामला दर्ज

मुंबई : प्रेमी अक्सर अपनी प्रेमिका को गुलदस्ता या महंगी चीजें तोहफे में देता है, लेकिन यहां एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। एक प्रेमी ने प्रेमिका को खुश करने के लिए ऐसा गिफ्ट दिया, जिससे दोनों पर मामला दर्ज हुआ और पहुंच गए जेल। मिली जानकारी के मुताबिक, अंधेरी स्टेशन से चर्चगेट की ओर जाने वाली फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक युवती सफर कर रही थी। डिब्बे में महिला टीसी सभी यात्रियों का टिकट चेक कर रही थी। टीसी ने जब युवती से टिकट मांगा तो उसने मोबाइल में मासिक पास दिखाया। पास यूटीएस ऐप से निकाला गया था और चर्चगेट से विरार तक एसी लोकल का था। पास का निरीक्षण करने पर महिला टीसी को कुछ संदेह हुआ तो उसने विभाग से कहकर जांच करवाई तो पता चला एसी का मासिक पास फर्जी है। फर्जी पास एआई की मदद से ३१ जनवरी २०२६ तक का बनाया गया था। पूछताछ में युवती संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो उसे बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उसने कबूल किया कि पास एआई की मदद से बनाया गया है। युवती से जब पूछा गया कि किसने फर्जी पास बनवाकर दिया तो उसने जो जानकारी दी, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। युवती ने बताया कि उसके प्रेमी ने उसे तोहफे में फर्जी एसी का पास दिया था। बांद्रा रेलवे पुलिस के मुताबिक, युवती और उसके प्रेमी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इन दिनों मुंबई में एसी लोकल के फर्जी पास के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर 4 ए, फ्लोर-जीआरडी, 29 डी, शबन हाउस, वंजावाडी लेन, माहिम वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhani.com